

भारत-द . कोरिया साझा व्यापार करेंगे

► द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर जोर

► समान मूल्यों वाले देशों के बीच सहयोग जरूरी

न्यूयॉर्क, कुआलालंपुर, वाशिंगटन, जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक और हाल ही में राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान हो चुकी है. उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रियों के रूप में उनकी जिम्मेदारी है कि वे दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाएं और विभिन्न सरकारी तथा आर्थिक क्षेत्रों के बीच सहयोग को बेहतर ढंग से समन्वित करें.

जयशंकर ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में समान विचारधारा, साझा मूल्यों और आपसी विश्वास रखने वाले देशों के बीच सहयोग पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है. उन्होंने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध इसी मजबूत आधार पर आगे बढ़ रहे हैं.विदेश मंत्री ने कहा कि हाल के महीनों में हुई



उच्चस्तरीय बैठकों, राष्ट्रपति यात्रा और जी7 जैसे मंचों पर हुई चर्चाओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान की है. उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देश इन अवसरों का लाभ उठाकर संबंधों की पूरी क्षमता को साकार करेंगे. जयशंकर ने चो ह्यून की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की भी

सराहना की. उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने शुरू से ही भारत-दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने की स्पष्ट इच्छा दिखाई है और भारत भी इस रिश्ते को समान महत्व देता है. उन्होंने भविष्य में और अधिक सकारात्मक एवं रचनात्मक चर्चाओं की उम्मीद जताई.

द. कोरिया के विदेश मंत्री ह्यून से मिले एस जयशंकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को सोल में अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष चो ह्यून से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच जहाज निर्माण, व्यापार, निवेश, रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, संस्कृति और पी2पी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की. दोनों ने स्टार्टअप्स, फिनटेक और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की. मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, 'विदेश मंत्री चो ह्यून से मिलकर अच्छा लगा. हमारी चर्चा हाल ही में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे य्युंग की भारत यात्रा के परिणामों पर आधारित थी. हमने दोनों देशों के बीच राजनीतिक, जहाज निर्माण, व्यापार, निवेश, रक्षा, तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, संस्कृति और जन-से-जन संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की.

महाराष्ट्र विधानसभा में 36,585 करोड़ की कर्ज माफी का ऐलान

मुंबई, 24 जून. महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 36,585 करोड़ रुपये की कृषि कर्ज माफी की घोषणा की है. सरकार के इस कदम से राज्य के 56 लाख से अधिक किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है. राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन इसकी घोषणा करते हुए कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने कहा कि यह पहल कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है. विधानसभा में नियम 293 के तहत हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्री भरणे ने कहा कि महायुति सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है. मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों के आश्वासनों के मुताबिक, हम एक व्यापक कर्जमाफी लालू कर रहे हैं. यह योजना वर्ष 2009, 2017 और 2019 के पिछले प्रयासों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है. सभी को साथ लेकर चलने के सरकार के रुख पर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इसी सत्र में महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तीकरण विधेयक पेश करेगी.

जरूरत पड़ी तो और समय लेंगे : पंत

► दान और वित्तीय लेन-देन में की जा रही निष्पक्ष जांच

► जांच के बिंदुओं को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता

लखनऊ, 24 जून. एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अयोध्या स्थित राम मंदिर से जुड़े दान और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर चल रही जांच एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है. तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर किया गया था, जिसका उद्देश्य मंदिर में प्राप्त होने वाले दान और वित्तीय लेन-देन में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच करना है.

जांच दल में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस. और वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरत्न शामिल हैं. टीम ने पिछले कुछ दिनों में मंदिर परिसर में उपलब्ध रिकॉर्ड, दानपत्रों की गिनती



जांच में दानपत्रों की गिनती प्रक्रिया, सोने-चांदी के आभूषणों के रिकॉर्ड और दान काउंटर पर प्राप्त उपहारों के प्रबंधन को लेकर कुछ प्रक्रियागत सवाल उठे हैं. हालांकि इन आरोपों या संदेहों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. एसआईटी ने संकेत दिया है कि यदि आगे जांच में अतिरिक्त दस्तावेज या नए तथ्य सामने आते हैं, तो इसके लिए सरकार से अतिरिक्त समय और संसाधनों की मांग की जा सकती है. साथ ही जरूरत पड़ने पर कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है.

प्रक्रिया, सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की विस्तृत जांच की है.

विजय विश्वास पंत ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि सौंपी हुई रिपोर्ट प्रारंभिक है और इसे सरकार के समक्ष केवल

तथ्यात्मक आधार पर प्रस्तुत किया गया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच के दौरान सामने आए सभी बिंदुओं को अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि मामला न्यायिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर संवेदनशील है.

नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक की अध्यक्षता करेंगे शाह

नई दिल्ली 24 जून. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को यहां नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे.

गृह मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से आयोजित यह बैठक सरकार के नशामुक्त भारत के विन को साकार करने के प्रयासों को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभायेगी। हाइब्रिड मोड में होने वाली बैठक में 44 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रमुख हितधारकों के साथ-साथ राज्य सरकारों और

मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 108 प्रतिनिधित्व हिस्सा लेंगे. इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री नशीले पदार्थ नियंत्रण पर विजन दस्तावेज (2026-2029) जारी करेंगे. केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों, नशीले पदार्थ प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया यह दस्तावेज नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए मांग कम करने, आपूर्ति कम करने और नुकसान कम करने के पहलुओं पर एक साझा रोडमैप प्रदान करेगा।

पीएम मोदी की बधाई पर गदगद हुए इथियोपिया के प्रधानमंत्री



कहा- मोदी मेरे विश्वसनीय मित्र और बड़े भाई

इथियोपिया, 24 जून. इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने चुनावी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली

बधाई के लिए आभार व्यक्त करते हुए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की इच्छा जताई है. उन्होंने मोदी को अपना 'विश्वसनीय मित्र और बड़े भाई' बताते हुए दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों की सराहना की. अबी अहमद अली ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक जनादेश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की लोकतांत्रिक शक्ति को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि इथियोपिया और भारत ऐतिहासिक संबंधों, साझेदारी और साझा आकांक्षाओं से जुड़े हुए हैं.

कोयले के आर्थिक मूल्यांकन पर केंद्र का बड़ा कदम

पर्यावरणीय लेखांकन को मजबूत करने की पहल

प्राकृतिक संसाधनों के आर्थिक मूल्य का आकलन

नई दिल्ली, 24 जून. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में कोयले के मौद्रिक परिसंपत्ति खातों के संकलन के लिए कार्य प्रणालीगत दृष्टिकोण ' शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया है. यह दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली केंद्रीय ढांचे के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने

पहल नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण

पर्यावरणीय संपत्तियों का मौद्रिक मूल्यांकन प्राकृतिक संसाधनों में निहित आर्थिक मूल्य का आकलन करने में मदद करता है. इससे संसाधनों के क्षरण की लागत का अनुमान लगाया जा सकता है, भविष्य में संसाधन निष्कर्षण से होने वाले सरकारी राजस्व का आकलन संभव होता है और विभिन्न पर्यावरणीय संपत्तियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को भी सुविधा मिलती है. राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में सतत खनन को अनिवार्य बनाए जाने के कारण यह पहल नीति निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय मानक के रूप में मान्यता प्रदान की है. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय वर्ष 2018 से एसईईए फ्रेमवर्क का अनुसरण करते हुए 'एनक्विस्टैट्स इंडिया' और 'एनजी स्टैटिस्टिक्स इंडिया' के माध्यम से कोयले तथा अन्य

एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी से मिलेगी यूपी के विकास को नई दिशा

बेंगलुरु/लखनऊ, 24 जून. उत्तर प्रदेश को तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल गवर्नंस के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बेंगलुरु में वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों और निवेशकों के साथ महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी रखा. इसी क्रम में उन्होंने गूगल क्लाउड के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी तरुण पंत और उनकी टीम के साथ विस्तृत चर्चा की. बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल गवर्नंस को लेकर व्यापक विचार-विमर्श किया गया.

एक नजर में 50 करोड़ के विकास कार्यों की रखी आधारशिला



जयपुर, 24 जून. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर क्षेत्र के संथीजी जैन मंदिर और सांगा बाबा मंदिर सहित 115 धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों की आधारशिला रखी. श्री शर्मा ने बुधवार को सांगानेर स्थित प्राचीन त्रिपोलिया बालाजी मंदिर में दर्शन किया और इस दौरान इन विकास कार्यों की आधारशिला रखी. उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना की. इस अवसर पर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झारब सिंह खत्री तथा अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे.

अमेरिका ने धोखाधड़ी नेटवर्क पर लगाये प्रतिबंध

वॉशिंगटन, 24 जून. अमेरिका ने कंबोडिया स्थित प्रिंस ग्रुप ट्रान्सनेशनल क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन से जुड़े नौ व्यक्तियों और 26 संस्थाओं पर कड़े प्रतिबंध लगा दिये हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर चल रहे साइबर धोखाधड़ी और धन शोधन नेटवर्क के खिलाफ अपने अभियान को और तेज कर दिया है. यह कार्रवाई अक्टूबर 2025 के उन वित्तीय प्रतिबंधों के बाद की गयी है, जिसके तहत प्रिंस ग्रुप टीसीओ और प्रिंस ग्रुप से जुड़े 146 व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रतिबंधित श्रेणी में डाला गया था. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थॉमस टैमी पिगोट ने कहा कि अमेरिका हड़ओने ग्रुप पर लागू होने वाले यूएसए पैट्रियट एक्ट की धारा 311 के तहत नियम बनाने की प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव कर रहा है, ताकि एच-पे सर्विस पीएलसी और हड़ओने ग्रुप की किसी भी संस्था के लिए अमेरिकी डॉलर खातों को प्रतिबंधित किया जा सके.

उच्चारण की गलतियों के लिए नार्वकर ने माफी मांगी

मुंबई, 24 जून. महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वकर ने बुधवार को सदन में सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव पढ़ते समय उच्चारण में हुई गलतियों के लिए बुधवार को माफी मांगी. श्री नार्वकर ने महान गांधिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि देते समय भाषा संबंधी गलतियों को लेकर विपक्ष की आलोचना का सामना करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की और कहा कि इस घटना के पीछे कोई गलत इरादा नहीं था. उन्होंने कहा, कि मुझे दिये गये शोक प्रस्ताव की छपी हुयी कोपी बहुत अस्पष्ट थी और उसमें फॉन्ट का आकार बहुत छोटा था. मैंने अनजाने में वैसा ही पढ़ा, जैसा वह दिख रहा था, जिससे गलतियां हुई. यह पूरी तरह से तकनीकी चूक थी. श्री नार्वकर ने मराठी भाषा और सदन की गरिमा के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता पर जोर दिया. उन्होंने कहा, कि मैं पिछले साढ़े चार वर्षों से सभी सदस्यों के सहयोग से इस सदन के अध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहा हूं. इस कार्यकाल के दौरान मैंने मराठी में कई सम्बोधन दिये हैं और कई शोक प्रस्ताव पेश किये हैं. इस सदन ने हमेशा अपना कामकाज मराठी में किया है और मैं अपनी मातृभाषा का बहुत सम्मान करता हूं. उन्होंने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कहा कि दिवंगत आशा भोसले जैसी हस्ती का अनादर करने के बारे में सोचना भी उनके लिए असंभव है.

हस्तियों के ट्वीट

भारत के एक जाने-माने युवा उद्यमी, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और देश के सबसे लोकप्रिय पॉडकास्टर राज शामानी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा करते कहा कि अपनी रोज की दिनचर्या को बार-बार बदलना, गहरे काम से बचने का एक छिपा हुआ तरीका है.

- राज शामानी

एलन स्पेसएक्स के संस्थापक, सीईओ एलन मस्क ने शल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा करते कहा कि डोज को केवल लाभार्थियों की संपर्क जानकारी की आवश्यकता थी ताकि यह पुष्टि की जा सके कि धन धोखाधड़ी से प्राप्त नहीं हुआ था. किसी भी मान्य चिकित्सा निधि को रोकना नहीं गया. -एलन मस्क

वेनेजुएला के तेल से अमेरिका को युद्ध की कीमत 28 गुना वसूल :ट्रंप

वॉशिंगटन, 24 जून. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका देश वेनेजुएला के तेल के जरिए वहां हुए अपने युद्ध की लागत से '28 गुना' पहले ही वसूल कर चुका है. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका इससे 'मोटी कमाई भी कर रहा है।' श्री ट्रंप ने कहा, उस युद्ध को जीतने में सिर्फ 48 मिनट लगे. हम वहां से लाखों बैरल तेल बाहर लेकर आये. यह आंकड़ा श्री ट्रंप के करीब एक हफ्ते पहले के पिछले दावे से अलग है.

लंदन कोर्ट में भगोड़े नीरव के बहाने फेल चुकाना होगा बैंक ऑफ इंडिया का 100 करोड़ का कर्ज : जज

नई दिल्ली, 24 जून. भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन हाई कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी को 10.7 मिलियन डॉलर (100 करोड़ रुपये से ज्यादा) का कर्ज चुकाने का आदेश दिया है.

लंदन की सर्किट कमर्शियल कोर्ट के जज साइमन टिकलर ने यह फैसला सुनाया. यह विवाद जुलाई 2012 में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नीरव मोदी की दुबई स्थित कंपनी फायररेक्टर डायमंड



एफजेडई को दिए गए एक लोन से जुड़ा है. नीरव मोदी ने 3 अगस्त 2013 को इस लोन के लिए खुद पर्सनल गारंटी दी थी. इसका मतलब था कि अगर कंपनी लोन नहीं चुकाती तो नीरव मोदी को

नेपाल में मिला प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान



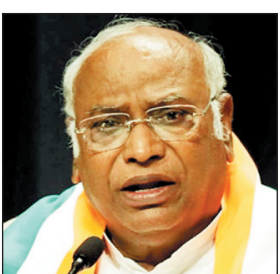
विभिन्न श्रेणियों में विद्वानों को अवार्ड भी दिए गए. इस संगोष्ठी में ही डॉ. कमल जीत सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, दयाल सिंह

खरगे ने की शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग

नई दिल्ली, 24 जून. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि देश में पेपर लीक का घटनाओं से करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है लेकिन सरकार छात्रों की चिंता को गंभीरता से लेने के बजाय उन्हें बहसाना करने का प्रयास कर रही है.

श्री खरगे ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि देश में 90 पेपरलीक हुए हैं और नीट पेपर लीक प्रकरण के कारण कई परिवार प्रभावित हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि श्री प्रधान छात्रों की आवाज को दहशतगद बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो भी सरकार से सवाल पृच्छा है, उसे देशद्रोही

कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के नेपाल में 'लोक चैतन्य सम्मान-2026' अवार्ड से सम्मानित किया गया.



छात्रों की आवाज दबाने का आरोप

या राष्ट्रविरोधी बताने की कोशिश की जाती है. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि छात्रों की गुंज पूरे देश में बुलंद होगी और कांग्रेस छात्रों तथा युवाओं के हितों की लड़ाई जारी रखेगी. उन्होंने दावा किया कि छात्रों के बढ़ते आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा.

भरत तिवारी एनकाउंटर केस में एसडीपीओ का तबादला पटना, 24 जून. भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार ने जगदीशपुर के एसडीपीओ का तबादला कर दिया है. लेकिन भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने साफ किया कि वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. गांववालों ने महापंचायत का ऐलान किया है. भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. जिस एनकाउंटर को परिवार फजी बता रहा है, उसी मामले में अब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो गया है. जगदीशपुर के एसडीपीओ को हटा दिया गया है और गांव में महापंचायत होने वाली है. एसडीपीओ राजेश वर्मा को पद से हटाकर अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है. ये एक्शन सीएम सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद हुआ है.

बंधुआ मजदूरी की घटना बर्बाद अर्थव्यवस्था का मलबा : राहुल

नयी दिल्ली, 24 जून. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सामने आए बंधुआ मजदूरी के मामले को बेहद चिंता के साथ बताया है कि यह सामान्य आपराधिक की घटना नहीं है बल्कि यह खस्ताहाल और धराशाई हुई अर्थव्यवस्था का मलबा है.

श्री गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मजदूरों से बिना मजदूरी दिए काम कराया गया, उन्हें कुत्तों से कटवाया गया, भाले से गोदा गया, कोड़े मारे गए और मवेशियों का चारा खिलाया गया. उन्होंने इसे इंसानी गरिमा पर सीधा हमला बताया और कहा कि



पीढ़ियों का न्याय के साथ पुनर्वास कर दौषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह भी पूछा जाना चाहिए कि मजदूर आखिर किन मजबूरियों में ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में फंस जाते हैं. जब रोजगार के अवसर समाप्त होते हैं, आमदनी उधर जाती है और मनरेगा तथा श्रम कानूनों जैसी सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं कमजोर कर दी जाती हैं.